Website : www.highwaychannel.in

छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्रसारित शाम का अखबार

हाईवे चैनल

वर्ष- 28 अंक- 94 रायपुर, मंगलवार 29 अप्रैल 2025 पृष्ठ-8 मूल्य- 2.50 रुपया • रायपुर • जगदलपुर से प्रकाशित RNI रजिस्ट्रेशन नं. 68139/98

एंटी नक्सल ऑपरेशन नहीं रुकेगा खात्मे की ओर नक्सलवाद : तोखन साहू

रायपुर, 29 अप्रैल (हाईवे चैनल)। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन 8 वें दिन भी जारी है। नक्सलियों के बड़े लीडरों को जवानों ने कर्रेगुट्टा की पहाड़ियों में घेर रखा है। इस मुठभेड़ में फ़ोर्स को बड़ी सफलता मिलने की उम्मीद है। इस बीच नक्सलवाद के खात्मे को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने बड़ा बयान दिया है।

केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खात्मे की ओर है, लेकिन कुछ नेता और दल माओवाद को सपोर्ट करने में लगे हैं। तेलंगाना की एक पार्टी ऑपरेशन रोकने की अपील कर रही है। लेकिन केंद्रीय अमित शाह ने टारगेट तय कर दिया ऑपरेशन रुकेगा नहीं। मार्च 2026 तक पूरा प्रदेश नक्सल मुक्त होगा। सरकार और जवान नक्सलियों के सामने शक्ति से कार्रवाई कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की सीमा कर्रेगुट्टा की पहाड़ियों ने बड़ी संख्या में जवानों ने डेरा डाला हुआ है। हेलीकॉप्टर से इलाके की निगरानी रखी जा रही है। यहां नक्सलियों के बड़े लीडरों के होने की आशंका है। जिसके मद्देनजर फ़ोर्स ने भी पूरी तैयारी के साथ घेराबंदी कर ली है। फिलहाल तीन महिला नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं, जिन पर 8-8 लाख का इनाम घोषित था।

यूपीएससी परीक्षा पास करने वाले प्रतिभागियों को मिलेंगे 1 लाख रुपए

रायपुर, 29 अप्रैल (हाईवे चैनल)। छत्तीसगढ़ में यूपीएससी की तैयारी कर रहे प्रतिभागियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार ने संघ लोकसेवा आयोग की मुख्य परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर नगरीय प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। बता दें कि राज्य शासन द्वारा नगर निगमों में महापौर सम्मान राशि दी जाती है। यूपीएससी के प्रतिभागियों को 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि इसी निधि के अंतर्गत दी जाएगी। हाल ही में यूपीएससी 2024 के नतीजे जारी हुए हैं, जिसमें बिलासपुर की पूर्वा अग्रवाल ने 65वां रैंक हासिल किया है।

मुंगेली के अर्पण चोपड़ा ने 313वां रैंक हासिल किया है। वहीं बस्तर के जगदलपुर की मानसी जैन ने 444वीं रैंक, अंबिकापुर के केशव गर्ग ने 496वीं रैंक और अंबिकापुर की ही शची जायसवाल ने 654वीं रैंक हासिल की है।

पहलगाम हमले के बाद 48 पर्यटक स्थल बंद

नई दिल्ली, 29 अप्रैल (न्यूज चैनल)। जम्मू-कश्मीर सरकार ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद बड़ा फैसला लिया है। जम्मू-कश्मीर में खुफिया सूचना के बाद 87 में से 48 पर्यटन स्थल बंद कर दिए हैं। सुरक्षा एजेंसियों की सिफारिश पर उमर सरकार ने यह फैसला लिया है।

जम्मू-कश्मीर सरकार ने खुफिया सूचना के बाद लिया फैसला

आतंकी हमलों की संभावना के बारे में खुफिया एजेंसियों की चेतावनी के बाद कश्मीर में 87 में से 48 पर्यटक स्थलों को बंद किया गया है। सूत्रों के अनुसार, पहलगाम हमले के बाद घाटी में कुछ स्लीपर सेल सक्रिय हो गए हैं, उन्हें गतिविधि शुरू करने के निर्देश दिए हैं। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकियों ने पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा कर 26 लोगों की नृशंस हत्या कर दी। सेना की वर्दी में आए दहशतगर्दों ने पहलगाम की बायसरन घाटी में पर्यटकों से पहले उनका धर्म पूछा, परिचय पत्र देखे और फिर हिंदू हो कहकर गोली मार दी। 26 मृतकों में ज्यादातर पर्यटक हैं, जबकि दो विदेशी और दो स्थानीय नागरिक शामिल हैं।

100 और 200 रुपये के नोट को लेकर आरबीआई का बड़ा फैसला, 1 मई 2025 से लागू होंगे नए नियम

नई दिल्ली, 29 अप्रैल (न्यूज चैनल)। भारतीय रिजर्व बैंक ने देशभर के बैंक ग्राहकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जो आने वाले समय में एटीएम उपयोग के तरीके को काफी हद तक बदल सकता है। इस नए फैसले का उद्देश्य आम जनता को रोजमर्रा के लेनदेन में राहत देना और कैश निकासी प्रणाली को अधिक व्यावहारिक बनाना है। हालांकि, इसके साथ ही एटीएम से पैसे निकालना कुछ लोगों के लिए थोड़ा महंगा भी पड़ सकता है।

रिजर्व बैंक द्वारा सोमवार को जारी एक सर्कुलर में स्पष्ट किया गया कि अब बैंकों और व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके एटीएम में छोटे नोटों की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में हो। इसमें खासतौर पर 100 और 200 रुपये के नोट शामिल हैं, जो कि आम लोगों द्वारा रोजमर्रा के खर्चों के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाते हैं। आरबीआई ने इस दिशा में चरणबद्ध रूप से बदलाव करने का निर्देश दिया है। नए निर्देशों के मुताबिक, 30 सितंबर 2025 तक देशभर में मौजूद 75 प्रतिशत एटीएम में कम से कम एक कैसेट में 100 या 200 रुपये के नोट मौजूद होने चाहिए। इसके बाद 31 मार्च 2026 तक यह अनुपात बढ़ाकर 90 प्रतिशत तक किया जाएगा।

दूसरी तरफ, 1 मई 2025 से एटीएम से पैसे निकालने की प्रक्रिया में एक और बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अब यदि ग्राहक अपनी फ्री लिमिट के बाद एटीएम से नकद निकालते हैं या बैलेंस चेक करते हैं, तो उन्हें ज्यादा शुल्क चुकाना पड़ेगा। अभी तक ग्राहकों को फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट खत्म होने पर प्रत्येक अतिरिक्त ट्रांजैक्शन के लिए 21 रुपये देने पड़ते थे, लेकिन इस शुल्क को बढ़ाकर 23 रुपये कर दिया गया है। यह बदलाव उन सभी ग्राहकों पर लागू होगा जो मेट्रो शहरों में तीन बार और अन्य स्थानों पर पांच बार फ्री ट्रांजैक्शन की सीमा पार करते हैं।

कमरे में खून से लथपथ मिला युवक का शव

रायपुर, 29 अप्रैल (हाईवे चैनल)। राजधानी रायपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. राजा तालाब इलाके में एक मकान के कमरे से युवक की संदिग्ध हालत में लाश बरामद हुई है. घटना की सूचना मिलते ही सिविल लाइन थाना पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के मुताबिक, मृतक की पहचान 50 वर्षीय रतनेश सागरकर के रूप में हुई है, जो अपने घर में अकेला रह रहा था. सोमवार देर शाम राजातलाब के कुंदरापारा इलाके स्थित उसके घर में खून से लथपथ शव पाया गया. शव के पास बिखरे खून और शव के शरीर पर चोटों के निशान पाए गए हैं, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है. प्रारंभिक जांच में पुलिस को यह अनुमान है कि रत्नेश की मौत दोपहर के समय हुई होगी। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस के साथ-साथ सीएसपी अजय कुमार भी मौके पर पहुंचे. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है और डॉग स्क्वाड की टीम को भी घटनास्थल पर बुलाया गया है. पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही हैं और इस मामले की गहनता से जांच कर रही है.

ब्रेकिंग न्यूज

खालिस्तान समर्थन एनडीपी गंवा सकती है राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा

नई दिल्ली, 29 अप्रैल (न्यूज चैनल)। कनाडा की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जगमीत सिंह ने बर्नबी सेंट्रल में अपनी सीट हारने और संघीय चुनाव में पार्टी के पतन के बाद अपने इस्तीफे की घोषणा की है। खालिस्तान के मुखर समर्थक सिंह अपने निर्वाचन क्षेत्र में तीसरे स्थान पर रहे, जो सीमा परिवर्तन से प्रभावित था। एनडीपी ने आवश्यक 12 सीटें जीतने में विफल रहने के बाद आधिकारिक पार्टी का दर्जा भी खो दिया। एनडीपी का नेतृत्व करना मेरे जीवन का सम्मान रहा है। मुझे पता है कि यह रात निराशाजनक है... लेकिन मैं अपनी पार्टी के लिए आशान्वित हूं, सिंह ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा। इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की टैरिफ धमकियों और कनाडा की संप्रभुता पर हमलों से प्रभावित अभियान के बाद प्रधान मंत्री मार्क कार्नी और लिबरल्स को सत्ता बरकरार रखने का अनुमान है।

देश के खुफिया चीफ तपन डेका पहुंचे छत्तीसगढ़, करेंगे गुप्त बैठक

रायपुर, 29 अप्रैल (हाईवे चैनल)। देश के खुफिया चीफ तपन डेका आज छत्तीसगढ़ पहुंचे. उनका छत्तीसगढ़ दौरा ऐसे मौके पर हुआ है, जब देश में आतंकी हमले की गूंज के बीच छत्तीसगढ़ में देश के सबसे बड़े नक्सल ऑपरेशन की चर्चा है. प्रदेश के बीजापुर जिला के कुर्रेगुटा पहाड़ी पर बीते 8 दिनों से नक्सल ऑपरेशन जारी है. और इस ऑपरेशन को छत्तीसगढ़ सहित तीन राज्य महाराष्ट्र और तेलंगाना के जवान अंजाम दे रहे हैं. ऑपरेशन में 10 हजार से अधिक जवान शामिल हैं. बताया जा रहा है कि पहाड़ी पर छुपे हुए 1500 नक्सलियों को जवानों ने घेर रखा है. इस ऑपरेशन को लेकर राज्य और केंद्र की सरकार अलर्ट है. इस बीच खुफिया चीफ का छत्तीसगढ़ दौरा होना बेहद अहम माना जा रहा है. सूत्रों के मुताबिक आईबी प्रमुख गुप्त रूप से एक हाईलेवल मीटिंग आलाधिकारियों की लेने वाले हैं.

बिरादरी की बातें

चूहा- सुनती हो, पीएम मोदी सर्वदलीय बैठक में नहीं आए।

चुहिया- हां जी, बिहार में चुनावी सभा भी तो बहुत जरूरी थी..!

पूर्व राज्यपाल अनुसुईया उइके के नाम से फर्जी पत्र मामला 5 साल बाद आरोपी गिरफ्तार

रायपुर, 29 अप्रैल (हाईवे चैनल)। छत्तीसगढ़ की पूर्व राज्यपाल अनुसुईया उइके के कार्यकाल के दौरान राजभवन में हुई एक जालसाजी के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। करीब 5 साल बाद मध्यप्रदेश की छिंदवाड़ा पुलिस ने आरोपी अजय वर्मा उर्फ अजय रामदास को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे लेने के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस रवाना हो गई है। बता दें कि सितंबर 2019 में छत्तीसगढ़ की तत्कालीन राज्यपाल अनुसुईया उइके के दस्तखत के साथ एक फर्जी पत्र वायरल हुआ था, जिसमें बीजेपी विधायकों की खरीद-फरोख्त की बातें लिखी गई थीं। इस पत्र के वायरल होने के बाद अनुसुईया उइके के निर्देश पर विशेष सचिव ने इसकी शिकायत सिविल लाइन थाने में की थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए सिविल लाइन थाने में तत्काल एफआईआर दर्ज कर इसकी जांच की जा रही थी, वहीं अब इस मामले में आरोपी को छिंदवाड़ा से गिरफ्तार किया गया है, जिसे लेने के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस छिंदवाड़ा रवाना हो गई है।

स्कूलों और शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया तेज

- स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी कलेक्टरों जारी किया पत्र
- संशोधित समय-सारणी के अनुसार होगी कार्रवाई

रायपुर, 29 अप्रैल (हाईवे चैनल)। छत्तीसगढ़ में स्कूलों और शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया तेज हो गई है. इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय ने दिशा-निर्देश भी जारी कर दिया है. इस संबंध में प्रदेश के सभी कलेक्टरों और जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजा गया है. विभाग द्वारा संशोधित समय-सारणी भी जारी की गई है, जिसके अनुरूप युक्तिकरण की कार्रवाई होगी।

जारी आदेश में विभाग ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुरूप शालाओं में शिक्षकों की उपलब्धता बच्चों की संख्या के अनुपात में सुनिश्चित की जानी चाहिए. वर्तमान में प्रदेश की कई शालाओं में सैकड़ों शिक्षक अतिशेष हैं, जबकि कई शालाएं शिक्षक विहीन या एकल शिक्षक प्रणाली पर निर्भर हैं. इस स्थिति में सुधार के लिए शालाओं और शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण छात्रहित में उचित बताया गया है। आदेश के अनुसार, उन स्थानों पर जहां एक ही परिसर में या निकटवर्ती क्षेत्र में दो या अधिक शालाएं संचालित हो रही हैं, उनका युक्तियुक्तकरण किया जाएगा. इसके साथ ही अतिशेष शिक्षकों को शिक्षक विहीन अथवा एकल शिक्षक शालाओं में समायोजित किया जाएगा. यह पूरी प्रक्रिया मंत्रिपरिषद् के दिनांक 09 जुलाई 2024 के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में संचालित की जाएगी. सभी संबंधित अधिकारियों को संशोधित समय-सारणी का पालन करते हुए शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

स्कूलों में युक्तियुक्तकरण का शिक्षक संघ ने किया विरोध, आंदोलन की तैयारी

रायपुर, 29 अप्रैल (हाईवे चैनल)। स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश के स्कूलों व शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण को लेकर दिशा-निर्देश व समय सारणी का आदेश समस्त कलेक्टरों के लिए जारी किया है. जिसको लेकर प्रदेश में फिर से बवाल मचने की संभावना है. क्योंकि इस निर्देश का शिक्षक संघ ने कड़ा विरोध किया है. शालेय शिक्षक संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र दुबे ने बयान जारी कर कहा कि यह स्कूलों, छात्रों, पालकों और शिक्षकों के साथ अन्याय है. उनका कहना है कि स्कूल व शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण के लिए जिन मापदंडों को तय किया गया है, वह वर्ष 2 अगस्त 2024 का पुराना आदेश है, जिसका मुखर विरोध शिक्षक संगठनों ने किया था. युक्तियुक्तकरण के पूर्व में जारी निर्देशों और मापदंडों पर तथ्यात्मक बहुत सारे सुझाव भी दिए थे. हालांकि तब यह प्रक्रिया सत्र के मध्य होने से अफरा-तफरी मच जाने की आशंका से स्थगित कर दी गई थी, परन्तु अब एक बार इसे प्रारंभ किया जा रहा है.

वीरेंद्र दुबे ने कहा कि युक्तियुक्तकरण के नाम पर स्कूलों के सेटअप से छेड़छाड़ किया जा रहा है. शिक्षक विहीन और एकल शिक्षकीय शालाओं में शिक्षकों की पदस्थापना अवश्य करना चाहिए पर स्कूलों के सेटअप से छेड़ाछाड़ कर प्राथमिक की 5 कक्षा के लिए प्रधानपाठक और एक शिक्षक से कैसे शिक्षा में गुणवत्ता आ सकती है ?

कल सीएम साय ने बुलाई मंत्रिमंडल की बैठक

रायपुर, 29 अप्रैल (हाईवे चैनल)। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल यानी 30 अप्रैल को मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है. यह बैठक मंत्रालय में आयोजित होगी, जिसमें सुशासन तिहार अभियान पर चर्चा की जाएगी. इसके अलावा मजदूर दिवस पर नई योजना शुरू करने पर भी विचार किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री साय 5 मई से प्रदेशभर का दौरा प्रारंभ करेंगे. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए रायपुर से जयपुर और दौसा के दौरे पर रहेंगे.

निगम में 'वन नेशन, वन इलेक्शन' का प्रस्ताव पारित

रायपुर, 29 अप्रैल (हाईवे चैनल)। रायपुर नगर निगम में आज 'एक देश, एक चुनाव' विषय पर विशेष सामान्य सभा आयोजित की गई इस सभा में प्रस्ताव पारित किया गया। इससे पहले धमतरी और बिलासपुर नगर निगमों में 'वन नेशन, वन इलेक्शन' का प्रस्ताव पहले ही पारित हो चुका है.

आने वाले दस वर्षों की जरूरत के हिसाब से पानी की व्यवस्था पर हो काम आउटर में विकसित हो रहे रिहायशी इलाकों में प्राथमिकता से उद्यान बनाएं: साय

- मुख्यमंत्री ने नगरीय प्रशासन विभाग के कार्यों की समीक्षा की
- अटल विश्वास पत्र पर प्रमुखता से अमल करने के दिए निर्देश, सभी शहरों की स्वच्छता रैंकिंग में हो सुधार

रायपुर, 29 अप्रैल (हाईवे चैनल)। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने मंत्रालय में आयोजित बैठक में विभाग द्वारा किए जा रहे बड़े कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने चालू वित्तीय वर्ष की प्राथमिकताओं पर चर्चा कर विभाग द्वारा संचालित केंद्र और राज्य शासन की योजनाओं के मैदानी स्तर पर क्रियान्वयन की भी जानकारी ली। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव और मुख्य सचिव अमिताभ जैन भी समीक्षा बैठक में शामिल हुए। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बैठक में अधिकारियों को शहरों में आने वाले दस वर्षों की जरूरत के हिसाब से पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने की कार्ययोजना बनाने और उन पर काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने शहरों के आउटर में विकसित हो रहे नए रिहायशी इलाकों में प्राथमिकता से उद्यान बनाने को कहा, ताकि बच्चों को खेलने-कूदने तथा बड़े-बुजुर्गों को वॉकिंग, जॉगिंग, योग और शारीरिक व्यायाम के साथ ही आमोद-प्रमोद की जगह सुलभ हो सके। मुख्यमंत्री ने सभी नगरीय निकायों में अटल विश्वास पत्र पर प्रमुखता से अमल करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी शहरों में साफ-सफाई की व्यवस्था दुरुस्त करते हुए भारत सरकार द्वारा जारी स्वच्छता की अपनी वर्तमान रैंकिंग में सुधार लाने को कहा। उन्होंने शहरों को सुंदर और स्वच्छ बनाने जन भागीदारी बढ़ाने के साथ ही इंदौर जैसे बेहतर सफाई व्यवस्था वाले शहरों में नगर निगमों के आयुक्तों को अध्ययन के लिए भेजने को कहा।

मुख्यमंत्री साय ने नगरीय प्रशासन विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए शहरी आबादी से सटे ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य विभागों से समन्वय बनाकर बुनियादी शहरी सुविधाएं विकसित करने को कहा। इससे निकट भविष्य में समीपवर्ती ग्रामीण इलाकों के नगरीय निकाय में शामिल होने या नए नगरीय निकाय के रूप में अस्तित्व में आने पर शहरों के मुताबिक व्यवस्थाएं और जन सुविधाएं विकसित करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में काम पूरा करने पर जोर देते हुए निर्धारित समयावधि में काम पूरा करने वाले निकायों के लिए रिवार्ड-सिस्टम बनाने का सुझाव दिया। उन्होंने निर्माण और विकास कार्यों की प्रगति की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए एप या ऑनलाइन सिस्टम तैयार करने को कहा। मुख्यमंत्री ने रायपुर नगर निगम की तरह अन्य नगरीय निकायों में भी संपत्ति कर की वसूली के लिए ऑनलाइन सिस्टम विकसित करने पर जोर दिया। इससे लोग घर बैठे या अपने कार्यस्थल से ही मोबाइल या कम्प्यूटर से संपत्ति कर जमा कर सकेंगे जिससे राजस्व संग्रहण में बढ़ोतरी होगी। उन्होंने अगले एक वर्ष में सभी निकायों में ऑनलाइन संपत्ति कर जमा करने की व्यवस्था तैयार करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने मोर संगवारी योजना के तहत घर पहुंच दस्तावेज बनाने की व्यवस्था को केंद्र सरकार के डिजी-लॉकर से लिंक करने को कहा। इससे नागरिकों के दस्तावेज स्थायी रूप से उनके डिजी-लॉकर में सुरक्षित रहेंगे। इससे योजना संचालन के व्यय में भी कमी आएगी। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने बैठक में बताया कि नगर निगमों के आयुक्तों तथा नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों द्वारा प्रतिदिन सवेरे निकाय के अधिकारियों के साथ साफ-सफाई एवं विकास कार्यों के निरीक्षण के अच्छे परिणाम आ रहे हैं।